भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न संख्या 1865**

दिनांक 29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

आर्थिक मंदी के मद्देनजर उद्योगों और रोजगार को संरक्षण

1865. **श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंहः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर देखी जा रही आर्थिक मंदी के दौर में, अधिकांश देश अपने रोजगार के अवसरों को सुरक्षित रखने, अपने उद्योगों को संरक्षण देने और अपने उत्पादकों का बचाव करने के लिय परम्परागत तरीकों के स्थान पर नये–नये तरीके अपना रहे है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व में इस प्रकार के प्रचलन ने विश्व व्यापार संगठन की भूमिका को किनारे पर लाकर रख दिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार इन बदलते हालात में भारत की विदेश व्यापार नीति पर पुनः विचार करेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया)

(क) यह रिपोर्ट दी गई है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के मद्देनजर परिष्कृत तकनीकी तथा पादप स्वच्छता विभिन्न प्रक्रियात्मक तथा प्रशासनिक कार्रवाई तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों की आड़ में उपायों सहित विभिन्न गैर-टैरिफ संरक्षणवादी उपायों का देशों द्वारा अधिकाधिक सहारा लिया जा रहा है । विश्व व्यपार संघ ने सूचित किया है कि अन्य बातों के साथ-साथ गैर-टैरिफ उपायों (एन टी एम एस) के महत्व में वृद्धि हुई है, जैसा कि वर्ष-दर-वर्ष टैरिफ नीचे आता गया है तथा लोक नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में उनका प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) एक खुली तथा नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था के लिए भारत सदैव तत्पर रहा है । जब कभी डब्ल्यू टी ओ सदस्य द्वारा किया गया कोई उपाय किसी डब्ल्यू टी ओ समझौतों का उल्लंघन होता है या व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसे समाधान हेतु डब्ल्यू टी ओ के उचित मंच पर ले जाया जाता है ।

(ग) एवं (घ) : वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में विशेषकर विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है । मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान व्यापार रक्षावादी का इस्तेमाल सीमित करने में तथा व्यापार प्रतिबंधित करने में डब्ल्यू टी ओ ने असंगत उपायों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । तथापि, डब्ल्यू टी ओ में व्यापार वार्ताओं के दोहा दौर में जिसका मुख्य उद्देश्य विकास कार्य से जुड़ा है,, अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है । भारत ने सदैव एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन किया है जो भेदभाव रहित, आशा के अनुरूप, पारदर्शी तथा विकास को समर्पित है । भारत समावेशी और समुचित तरीके से व्यापार से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है ।

(ड.) उद्योग की आवश्यकताआ, वैश्विक आर्थिक स्थितियों तथा डब्ल्यू टी ओ के वचनबद्धताओं के आधार पर नियमित रूप से भारत की व्यापार नीति और स्कीम तैयार की जाती है तथा अद्यतन की जाती है । 5 जून 2012 को विदेश व्यापार नीति 2009-14 के वार्षिक पूरक 2012-13 की घोषणा की गई थी ।